



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 7 जुलाई, 2021

आषाढ़ 16 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास विभाग

संख्या 1001/77-3-2021-90(एम)-2020

लखनऊ, 7 जुलाई, 2021

अधिसूचना

प0आ0-154

चूं कि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 68/77-3-2021-90(एम) -2020, दिनांक 27 जनवरी, 2021 एवं शुद्धि पत्र संख्या 337/77-3-2021-90(एम) -2020, दिनांक 17 फरवरी, 2021, लोक प्रयोजन, अर्थात् उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधि करण के माध्यम से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के द्वितीय चरण हेतु जिला झांसी, तहसील -गरौठा स्थित ग्राम नैकेरा में 21.5483 हेक्टेयर, लभेरा में 6.77975 हेक्टेयर, कठरी में 0.0203 हेक्टेयर कुल 28.34835 हेक्टेयर भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उप धारा (1) के अधीन जारी की गई थी। झांसी के कलेक्टर को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (2) के अधीन परन्तुक अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिपोर्ट पर

विचार करने के पश्चात्, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) के अधीन घोषणा करती हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा -प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (2) के अधीन कलेक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेश देती हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। (जिला झांसी में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।)

### अनुसूची "क"

प्रस्तावित अर्जन के अधीन भूमि

क्रम संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	झांसी	गरौठा	गरौठा	नैकेरा	50	0.0858
2					69	0.6110
3					70	0.8430
4					73मि .	0.1460
5					137	1.2150
6					139	0.9105
7					147	0.2280
8					151	3.5570
9					158	2.1770
10					275	5.5690
11					279	0.0160
12					285	1.7160
13					286	0.1660
14					288	0.0890
15					289	0.1370
16					291	0.0690
17					292	0.1300
18					293	0.4410
19					417मि .	0.2020
20					417मि .	0.2090
21					423मि .	0.3890
1	2	3	4	5	6	7
22					423मि .	0.0690

23					431	2.5730
24					<b>योग</b>	<b>21.5483</b>
25	झांसी	गरौठा	गरौठा	लभेरा	369	0.3320
26					372	1.3080
27					372/2	0.5180
28					375	2.2060
29					378	1.6370
30					436	0.5910
31					438	0.15575
32					391	0.0080
33					392	0.0080
34					405	0.0160
35					<b>योग</b>	<b>6.77975</b>
36	झांसी	गरौठा	गरौठा	कठरौ	259	0.0203
					<b>योग</b>	<b>0.0203</b>
					<b>कुल योग</b>	<b>28.34835</b>

**अनुसूची "ख"**  
**विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिनिहत भूमि**

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाना वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
झांसी	गरौठा	गरौठा	नैकेरा	शून्य	शून्य
			लभेरा	शून्य	शून्य
			कठरौ	शून्य	शून्य

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है।)

**टिप्पणी :-**उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, झांसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,  
अरविन्द कुमार,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1001/LXXVII-3-2021-90(M)-2020, dated July 7, 2021 :

No. 1001 /LXXVII-3-2021-90(M)-2020  
Dated Lucknow, July 7, 2021

WHEREAS preliminary notification no. 68/LXXVII-3-2021-90(M)-2020 dated January 27, 2021 and Corrigendum no. 337/77-3-2021-90(M)-2020, dated February 17, 2021 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), in respect of total 28.34835 Hectares of land in the Village Naikera 21.5483 Hect., Labhera 6.7795 Hect., Kathri 0.0203 Hect., Tehsil Garautha, District Jhansi. for public purpose, namely Second phase of Defence Industrial Corridor Project through Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority. The Collector Jhansi was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

NOW, THEREFORE, after considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the said Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the Schedule "A" below is needed for public purpose and no land in the Village, Paragana and District as given in Schedule "B" has been identified for Rehabilitation and Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the said Act to direct the Collector to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith. (No family is likely to be displaced due to land acquisition for of Defense Industrial Corridor Project in district Jhansi. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation & Resettlement and publication of summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme.)

#### SCHEDULE-A

##### Land Under Proposed Acquisition

Sl.No.	District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hact.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jhansi	Garautha	Garautha	Naikera	50	0.0858
2					69	0.6110
3					70	0.8430
4					73मि .	0.1460
5					137	1.2150
6					139	0.9105
7					147	0.2280
8					151	3.5570
9					158	2.1770
10					275	5.5690
11					279	0.0160
12					285	1.7160
13					286	0.1660
14					288	0.0890

1	2	3	4	5	6	7
15					289	0.1370
16					291	0.0690
17					292	0.1300
18					293	0.4410
19					417मि .	0.2020
20					417मि .	0.2090

21					423मि .	0.3890
22					423मि .	0.0690
23					431	2.5730
24					<b>Total</b>	<b>21.5483</b>
25	Jhansi	Garautha	Garautha	Labhera	369	0.3320
26					372	1.3080
27					372/2	0.5180
28					375	2.2060
29					378	1.6370
30					436	0.5910
31					438	0.15575
32					391	0.0080
33					392	0.0080
34					405	0.0160
35					<b>Total</b>	<b>6.77975</b>
36	Jhansi	Garautha	Garautha	Kathri	259	0.0203
					<b>Total</b>	<b>0.0203</b>
					<b>Grand Total</b>	<b>28.34835</b>

SCHEDULE-B  
Land Identified As Settlement Area For Displaced Families

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hact.)
1	2	3	4	5	6
Jhansi	Garautha	Garautha	Naikera	0	0
			Labhera	0	0
			Kathri	0	0

(No family is likely to be displaced, due to land acquisition for this project.)

NOTE :- A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Jhansi.

By order,  
ARVIND KUMAR,  
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 109 राजपत्र-2021-(205)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० औद्योगिक विकास-2021-(206)-250-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।